etc., likely to be lost sight of by the road authorities concerned in the midst of other activities. Feeder roads in rural areas do not, however, specifically fall within the purview of these objectives. Even the programme for construction of rural roads under the Revised Minimum Needs Programme is in State Sector and there is no Central Scheme or Centrally Sponsored Scheme for providing financial assistance for construction of rural roads. The Planning Commission have recommended a total outlay of Rs. 1164.90 crores in the Sixth Five Year Plan for construction of Rural Roads under the Revised Minimum Needs Programme in the State Sector.

New rail lines

7106. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names and particulars of proposals received from various State Governments for laying new railway lines which are under consideration or have not been found feasible propositions;

(b) the reasons for discarding the proposals; and

(c) the various stages at which each proposal is lying at present?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. Placed in Library. [See No. LT-2334/81].

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना और उनमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना

7107. श्री बालासाहिब विखे पाटिल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशु तथा उसकी माता को परिवार नियोजन आपरेशन के बाद उनका स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु क्या सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर): ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी सलाह, सेवाएं और सामग्री अब बड़ी संख्या में उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनके साथ परिवार कल्याण यूनिट भी सम्बद्ध हैं, तहसील और जिला स्तर के अस्पतालों, जिनमें से कुछ के साथ प्रसवोत्तर केन्द्र संलग्न हैं, के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती हैं। जिला स्तर पर बाल चिकित्सा यूनिट भी खोल दिए गए हैं। छठी योजनावधि, 1980-85, में इनका विस्तार करके इनमें 300 तहसील स्तर के प्रसवोत्तर केन्द्र 174 दर्जा बढ़ाये गए ग्रामीण अस्पताल, 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1000 सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और 40,000 उपकेन्द्र और जोड़ने का विचार है।

हर गांव में एक-एक प्रशिक्षित दाई उपलब्ध हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए छठी योजना (1980-85) के दौरान गांवों में प्रसव कराने वाली परम्परागत दाइयों के प्रशिक्षण की योजना जारी रखी जाएगी।

इन योजनाओं में से केन्द्रीय सरकार तहसील स्तर पर 300 प्रसवोत्तर केन्द्रों, 40,000 उपकेन्द्रों के प्रस्तावित विस्तार तथा दाइयों के प्रशिक्षण के लिए धन की व्यवस्था करेगी और अन्य गतिविधियां राज्यों की योजनाओं में शामिल हैं।

ब्रिटेन में जातीय भेदभाव

7108. श्री राम अवध : क्या विदेश यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारत मूल के लोगों तथा भारतीय प्रवासियों के प्रति जातीय

भेदभाव तथा परेशान किये जाने की घटनायें पिछले कुछ समय में बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने मामले पिछले तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ऐसे संकेत हैं कि हाल ही में एशियाईयों को, जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं, जातीय-स्तर पर तंग किए जाने और उन पर आक्रमण किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(ख) विगत तीन वर्षों में भारतीय हाई कमीशन की जानकारी में जो मामले आये हैं, उनका वर्षवार ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है—

1978 —2 मामले जिसमें चार भारतीय शामिल थे;

1979—3 मामले जिनमें 156 भारतीय थे, इसमें अप्रैल, 1979 में साउथाल के दंगों में प्रभावित 153 भारतीय भी शामिल हैं।

1980—7 मामले, इनमें 6 मामलों में 9 भारतीय प्रभावित हुये और 7वें मामले में भारतीय मूल के करीब 50 व्यक्ति प्रभावित हुये।

मार्च 1981 तक—2 मामले जिनमें दो भातीय प्रभावित हुये।

(ग) हाई कमीशन की जानकारी में ऐसे जितने भी मामले आए थे जिनमें भारतीय प्रभावित हुये थे, उन सबको सम्बद्ध कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। भारतीयों पर आक्रमण के अधिकांश मामलों में पुलिस की छानबीन के बावजूद दोषी व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जा सका। बहरहाल, हाई कमीशन प्राधिकारियों के साथ और भारतीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ निकट सम्पर्क रखता है। इस सम्बन्ध में, फरवरी 1981 में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने जातीय आधार पर किए गए कुछ आक्रमणों के लिए जिम्मेदारी उग्रवादी ग्रुपों की गतिविधियों की विभागीय जांच शुरू करवा दी है और यह घोषणा की है कि उनके अधिकारी इस समस्या का अध्ययन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

Restructure of costing system

7109. SHRI N. K. SHEJWALKAR: SHRI S. M. KRISHNA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway Board propose to restructure the costing system now prevalent in the Railways;

(b) whether, in determining the new cost basis, the Railways are understood to have laid more emphasis on viability; and

(c) if so, in what way the present structure has been found wanting and the directions in which Government propose to move in determining the new cost system?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) There is no proposal at present to restructure the costing system.

(b) and (c) Do not arise.

Second class waiting rooms in Kerala stations

7110. SHRI V. S. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many railway stations in Kerala do not have adequate waiting rooms facilities for the second class passengers;